



VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2205)

Name of Candidate	ANKIT KUMAR JAIN		
Medium Eng./Hindi	HINDI	Registration Number	649298
Center	JAIPUR	Date	19-06-22

INDEX TABLE			INSTRUCTIONS
Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained	
1	10		1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code). उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)। 2. There are TWENTY questions printed in ENGLISH & HINDI इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं। 3. All questions are compulsory. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it. प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं। 5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one. प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। 6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to. प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए। 7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off. उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।
2	10		
3	10		
4	10		
5	10		
6	10		
7	10		
8	10		
9	10		
10	10		
11	15		
12	15		
13	15		
14	15		
15	15		
16	15		
17	15		
18	15		
19	15		
20	15		
Total Marks Obtained:			
Remarks:			

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar
Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

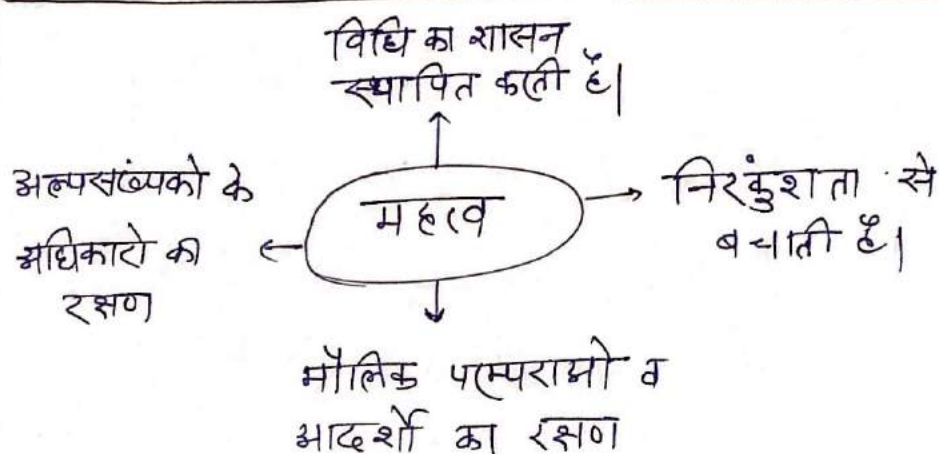
5.

6.

All the Best

1. What do you understand by 'constitutionalism'? Highlight various ways in which the Indian Constitution underscores this principle. (150 words) 10
- 'संविधानवाद' से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को रेखांकित करने वाले विभिन्न उपबंधों पर प्रकाश डालिए।

संविधानवाद : वो उपबन्ध भयवा प्रावधान जो किसी सरकार के विवेकाधिकार को सीमित करता है, संविधानवाद है।



भारतीय संविधान में संविधानवाद

- ① अनुच्छेद - 13 : मौलिक अधिकार (भाग 3) का उल्लंघन करने वाली विधियाँ शून्य।
- ② अनुच्छेद - 32 तथा अनुच्छेद - 226
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को

रिट जारी करने का अधिकार ।

(रिट के प्रकार — बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश
— प्रसिधेय, उत्प्रेषण
— अधिकार पृच्छ)

3. अनुच्छेद - 31 — अल्प किसानों की सिंचित भूमि
का अधिग्रहण से पूर्व मुद्दावजा

तथा अनुच्छेद - 30 — अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानें

4. अनुच्छेद - 266 — बिना विधि के प्रावधान के
किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकते।

5. समानता का अधिकार (अनुच्छेद-14 से अनुच्छेद-19)

6. स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद-19 से अनुच्छेद-22)

7. अनुच्छेद-20 ⇒ आपराधिक कानून से पूर्व विधि से
8. - लागू नहीं होना ।

8. अनुच्छेद - 324 तथा 325 ⇒ मतदाता के अधिकार

अतः भारतीय संविधाननिर्माताओं ने
पर्याप्त प्रावधान करके संविधानवाद के लक्षणों से
तानाशाहभुक्त शासन-प्रशासन बनाया है। परन्तु
आपातकालीन प्रावधान इसमें संदेह उत्पन्न करते हैं।
44 वे संविधान संशोधन तथा एस.आर. बोम्मई वाद
में उच्चतम न्यायालय ने पुनः सरकार की विवेकाधीन
शक्तियों को कम कर संविधान के मौलिक अधिकारों को स्थापित किया।

2. With adequate arguments and examples, elaborate your views on whether interest and pressure groups in India are undermining democracy or strengthening it. (150 words) 10

पर्याप्त तर्कों और उदाहरणों के साथ, सविस्तार अपने विचार व्यक्त कीजिए कि क्या भारत में हित समूह और दबाव समूह लोकतंत्र को दुर्बल कर रहे हैं या इसे सुदृढ़ कर रहे हैं।

हित समूह और दबाव समूह :

किसी विशेष

हित अथवा विषय कर समान मत रखने वाले लोगों का समूह। उ० :-

उदा. किसान - भारतीय किसान संघ
- शेतकारी संगठन

मजदूर - भारतीय मजदूर संघ
- ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस

व्यापारी - कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्री
- एसोसिएम - फिक्की

लोकतंत्र को दुर्बल कर रहे हैं

1. निजी हितों को राष्ट्रीय हितों से

अधिक महत्व। उदा. - रिटेल क्षेत्र में एफडीआई का ~~खुला~~ विवाद।

2. चुनावी हितों को प्रभावित करना।

उदा. - किसान बिल पर विवाद

- ③ अन्य कमजोर वर्गों के हितों की अनदेखी होना। — श्रमिक वर्गों की अनदेखी
- ④ प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप बढ़ना।

लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं

① विशेषज्ञ सेवाएँ- प्रदान कछे नीति निर्माण में। उदा.- नियति नीति, अमनीति

② जन सहभागिता बढ़ाते हैं।

↳ सच्चे व व्यापक अर्थों में लोकतंत्र

उदा.- शिक्षा नीति का निर्माण।
उदा.- शिक्षा नीति पर सबसे बड़ा विमर्श होना।

③ प्रशासनिक अनदेखियों अनदेखीयों तथा

गलत निर्णयों का पुनः सुधार करना।

उदा.- किसानों ~~बिचों~~ से जुड़े अग्रनिर्णयों का वापस लेना।

हालाँकि आजादी के बाद से ही दबाव समूहों ने भारत में सरकारों को सहयोग किया है, परन्तु कई बार निजी हितों ने कई महत्वपूर्ण सुधारों को रोक रखा है। अतः सरकार को व्यापक इस्तिमोश तथा सर्वजन हिताय - सर्वजन सुखाय को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों से सलाह लेकर कार्य करना चाहिए।

3. The Competition Commission of India (CCI) effectively reflects a shift from the era of Licence Raj to a conducive regulatory ambience for enhancing consumer welfare by encouraging competition in the market. Discuss.

(150 words) 10

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाने के लिए लाइसेंस राज के युग से एक अनुकूल नियामकीय परिवेश में स्थानांतरण को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। चर्चा कीजिए।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 से निमित्त स्लीसीआई ने एमआरटीपी अधिनियम का स्थान लिया।

प्रभाव

↳ ① एकाधिकार को रोकने के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना देना।

↳ सकारात्मक इलिकोण

② निजीकरण के अनुकूल माहौल विकसित करना।

③ निवेशकों के अनुकूल कम्पनी अधिनियमों का पालन सुनिश्चित करना।

④ भारतीय बाजारों में उपभोक्ता हितों-

तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के

अनुकूल कम्पनीयों को कार्य करना।

⑤ प्रीदेररी प्राइस, कोर्टेलाइजेशन का नियंत्रण।

- ⑤ कम्पनी के विलय, हिस्सेदारी के अरीक-
विक्री को विनियमित कर छोटे निवेशकों
की रक्षा करना।

हालांकि कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ भारतीय
प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्य चुनौतीपूर्ण रहा है -
जैसे -

- ① भारत में ऑनलाईन उपस्थिति रखने
वाली कम्पनियों पर विनियमन
- ② लॉटरी, जुआ- जैसी गतिविधियों का
विनियमन
- ③ हच - वोडफोन तथा एस्सार डील में
भारतीय हितों की अनदेखी।
- ④ रिनायरस पथूचर डील विवाद।

अतः ऐसे विवादों में भारतीय उपभोक्ताओं के
हितों की रक्षा हेतु कई कदम उठाने चाहिए

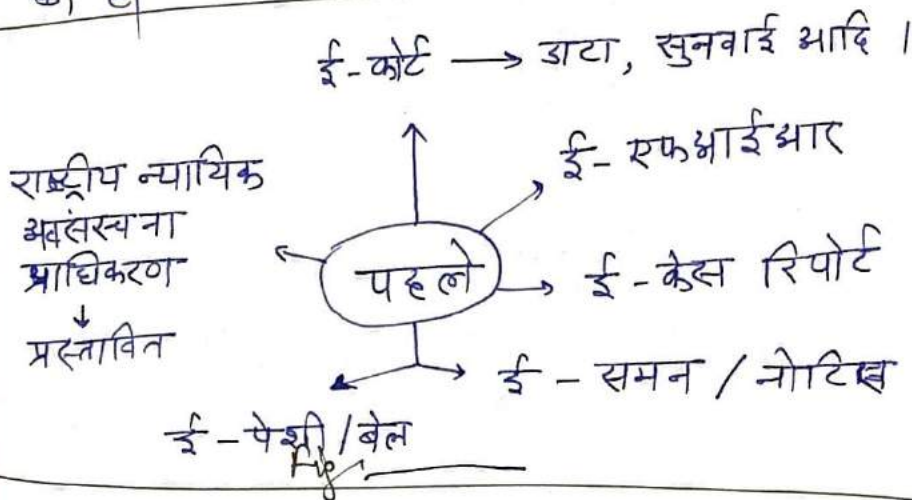
- जैसे - ① कम्पनियों के लिए एस्.ओ.पी. का निर्माण
② विधिक प्रावधानों को प्रभावी तथा व्यापक बनाना
③ कार्यक्षमता में सुडि → विदेशी नियामक संस्थाओं से
तालमेल बढ़ाना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।

सीरिआई जैसी संस्थाओं के शानदार कार्यों
को और आगे बढ़ाते हुए निवेशकों के अनुकूल माहौल
को विकसित करना चाहिए ताकि अधिक सुडि और अधिकतम
हो सकें।

4. Mention various initiatives taken for online delivery of judicial services in India. Also, discuss the challenges faced in their implementation. (150 words) 10

भारत में न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी के लिए प्रारंभ विभिन्न पहलों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

24 वीं ई-गवर्नेंस कार्यशाला में
दोषित हैदराबाद धोषणापत्र में एक आयाम
न्यायिक सेवाओं की ऑनलाईन से भी जुड़ा है
इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय के
न्यायाधीश जी.वाई. लख्खड़ की अध्यक्षता में
समिति ने भी इस सम्बन्ध में कई अनुसंधान
की हैं।



- * दिल्ली उच्च न्यायालय → जीरो पेडिस्ली प्रोजेक्ट
- * सभी न्यायालयों को उच्च गति की फाइबर केबल से जोड़ना।

चुनौतियाँ

- ① डिजिटल डिवाइड
- ② तकनीकी कौशल का अभाव
↳ न्यायाधीशों और अधिकारियों में।
- ③ तकनीकी अवसंरचनाओं की कमी।
- ④ भौगोलिक पहुँच की बाधा — उत्तर-पूर्वी भारत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में
- ⑤ मनोवृत्ति का अभाव
- ⑥ डाटा संरक्षण की निम्न सुरक्षा से जुड़ी चुनौती।
↳ निजता का अधिकार (अनु-21; पुनर्जागरण बाद)

आगे की राह

- ① तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना।
- ② अवसंरचना में विस्तार → डिजिटल इण्डिया मिशन
→ नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन

③ प्रशिक्षण

- ④ डाटा संरक्षण अधिनियम को लागू करना

उच्चतम न्यायालय के अनुसार 3.5 करोड़ से अधिक बजट न्यायालयों में विचारधीन हैं जिस कारण 2-4% GDP को मुहलान बढ़ेगा है (CAG)। अतः न्यायिक सेवा के ऑनलाईन होने से समय, पैसा तथा क्षमता की बचत होगी जो अन्य उत्पादक कार्यों में लगाकर अधिक प्रगति की जा सकती है।

5. Bring out the similarities and differences in the Bill of Rights in the Constitution of the United States and Fundamental Rights in the Constitution of India. (150 words) 10

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उपबंधित बिल ऑफ राइट्स और भारत के संविधान में मूल अधिकारों के मध्य समानताओं और भिन्नताओं को रेखांकित कीजिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं सदी के अंतिम दशक में मौलिक अधिकार संविधान में 'बिल ऑफ राइट्स' के नाम से नागरिकों को दिए हैं। जबकि भारतीय संविधान के भाग - 3 में यह वर्णित है।

समानता

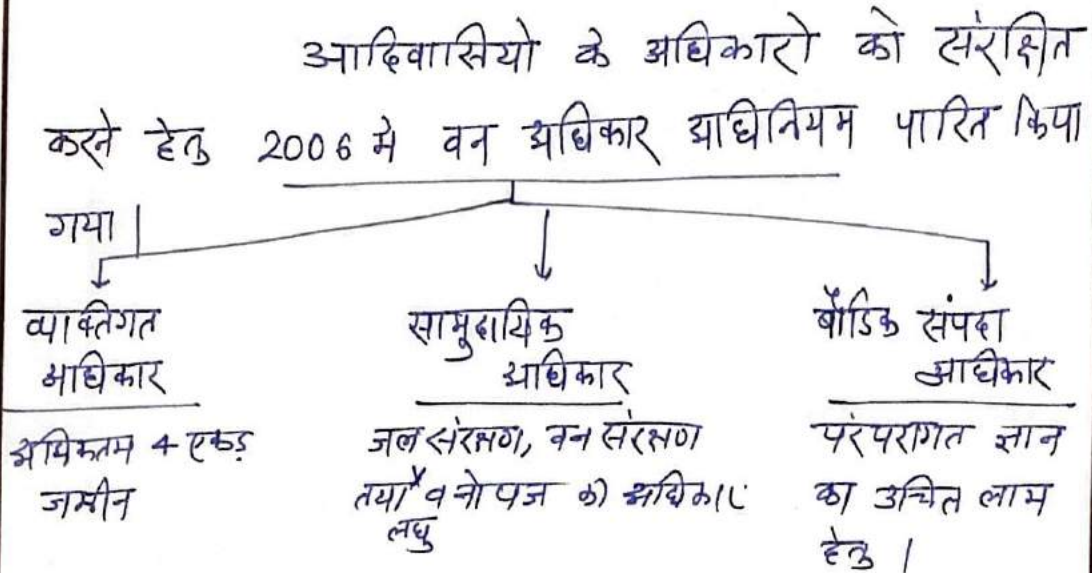
- ① समानता का अधिकार
भारत में - जाति, धर्म, रंग, नस्ल, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं।
अमेरिका - धर्म, नस्ल, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं।
- ② ~~सम्यक्~~ व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
- ③ न्यायिक समीक्षा का प्रावधान
भारत में - अनुच्छेद - 13
- ④ भारत में → अनुच्छेद - 21 विधि का सम्यक् प्रकार से निर्माण (ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ)
अमेरिका - सम्पूर्ण विधि निर्माण में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
- ⑤ ~~मूल~~ मूल अधिकारों के हनन पर न्यायालय की शरण का प्रावधान।

मिन्नतार	भारत	यू.एस.ए.
①	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर न्यायिक समीक्षा। (सिवाय अनुच्छेद-21) ↓ (मेनका गांधी कास)	विधि की सम्पूड निर्माण (इयू प्रोसेस ऑफ लॉ) द्वारा न्यायिक-समीक्षा। ↓ अधिक विस्तारित → न्यायिक सर्वोच्चता
②	मूल अधिकारों के हनन पर संघ/राज्य दोनों खिलाफ उच्चतम या उच्च न्यायालय दोनों में जाने का प्रावधान। (अनु. - 32 तथा 226)	मूल अधिकारों के हनन पर संघ के खिलाफ - संघीय कोर्ट राज्य के खिलाफ - प्रांतीय कोर्ट

ब्रिटेन के 13 वीं सदी में प्रस मँगनाकारों से शुरू हुए मौलिक अधिकारों ने व्यक्ति की गरिमा और जीवन के अधिकारों का संरक्षित रखते हुए तानाशाही और निरंकुशता से बचाया है। यही कारण है कि USA तथा भारत दोनों ही राष्ट्र लोकतंत्र के मामले सफल राष्ट्रों में शुमार होते हैं।

6. It is often argued that the implementation of The Forest Rights Act (FRA), 2006 has so far been tardy and ineffectual. Discuss. (150 words) 10

प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि अभी तक वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का कार्यान्वयन धीमा और निष्प्रभावी रहा है। चर्चा कीजिए।



उचित कार्यान्वयन न होने के कारण

- ① प्रक्रियात्मक जटिलताओं का होना।
↳ त्रिस्तरीय जांच का होना, तीन विभागों का (वन, जनजाति, (प्रस) समन्वय न होना
- ② आदिवासियों में जागरूकता का न होना।
- ③ अधिकारियों की जवाबदेही का न होना।
↳ समयबद्ध प्रक्रिया नहीं।
- ④ राजनीतिक गोलबंदी का शिकार होना।
- ⑤ दस्तावेजों का अभाव होना; जिससे वहाँ के आदिवासी बता पाना मुश्किल।

⑥ प्रशासनिक मनोवृत्ति का वकारात्मक होना।

सुधार हेतु उठाए जाने वाले कदम

- ① नियमों में सरलताएं तथा उसका आदिवासी-भाषा में रूपांतरण करना।
- ② प्रक्रियात्मक जटिलताओं का सरलीकरण।
- ③ विभिन्न एनजीओ जैसे - वनवासी आश्रम, सार्पिक, वनमाला आदि का सहयोग लेना।
- ④ प्रशासनिक गवाबदेही तथा समबन्ध निपटान सुनिश्चित करना।

महत्व

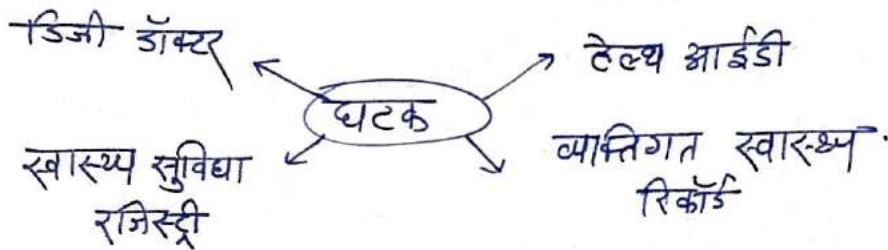
- ① अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या - 7-8% है तथा उनका जीडीपी में योगदान 3% से भी कम है।
- ② भू-अधिकारों, लघुवनोपज अधिकारों से आर्थिक स्रोतों का सूजन तथा उसमें निवेश के अवसर बंद होने से गरीबी, बेरोजगारी कम होगी तथा शिक्षा व स्वास्थ्य तथा पोषण का स्तर बढ़ेगा।
- ③ आय में वृद्धि से वनों का अत्यंत दोहन रुकेगा जो भारत के संयुक्त कार्बन स्टॉक में वृद्धि सुनिश्चित होगा। अतः संकटापन्न अर्थ-की पालना न केवल विधिक बालिग नैतिक जिम्मेदारी भी है।

7. The National Digital Health Mission (NDHM) has the potential to bring a new revolution in India's health sector in multiple ways. Explain.

(150 words) 10

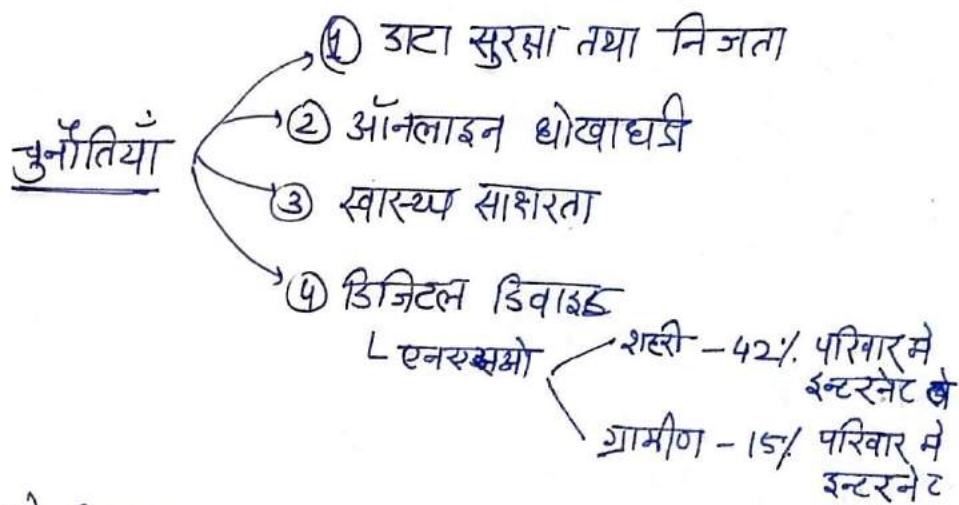
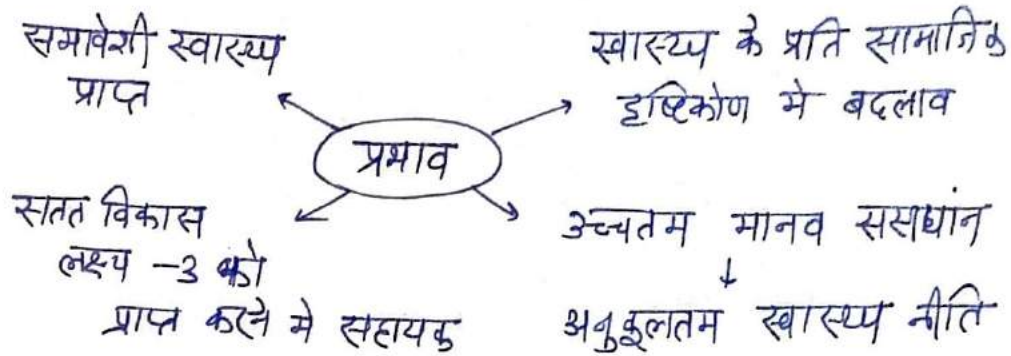
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई तरह से एक नई क्रांति लाने की क्षमता है। व्याख्या कीजिए।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को साकार करने हेतु 2020 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई।



क्रांतिकारी कदम

- ① स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
- ② महामारी के दौर में भी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता रहेगी।
- ③ स्वास्थ्य डाटा होने से → उत्कृष्ट स्वास्थ्य नीति निर्माण
- ④ बेहतर व तार्किक रूप स्वास्थ्य खर्च हो सकेगा
- ⑤ दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य ऑनलाईन।
- ⑥ रोगों की निगरानी में।
- ⑦ स्वास्थ्य सेवाओं तथा पोषण में वृद्धि से मानव संसाधन
- ⑧ की गुणवत्ता उत्तम होगी → आर्थिक इंजन का काम
- ⑧ डॉक्टर की सूची व सुविधाओं के विस्तार में।



भाग्य की राह:

- ① एनडीएचएम रोगी के साथ स्वास्थ्य सुविधा प्रदाताओं की जानकारी भी देता है, अतः स्वास्थ्य नीति निर्माण का मुख्य केंद्र बिन्दु बनेगा।
- ② इसके विस्तार हेतु कॉमन सर्विस सेन्टर जैसे स्वास्थ्य सेवा केंद्र दूरस्थ तथा उर्ध्व क्षेत्रों में शुरू हो सकते हैं।
- ③ डाटा सुरक्षा हेतु विधिक तथा संस्थागत उपबंध किए जाने चाहिए।

एनडीएचएम अलाव में लंबे समय से प्रस्तावित एक क्रांतिकारी योजना है जो संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा में बड़े बदलाव आने में सक्षम होगी।

8. Explain the rationale behind the creation of a Social Stock Exchange in India. Do you think this move would boost social impact investing in the country? (150 words) 10

भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के सृजन के पीछे निहित तर्क की व्याख्या कीजिए। क्या आपको लगता है कि इस कदम से देश में सामाजिक प्रभाव वाले निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त होगा?

सोशल स्टॉक एक्सचेंज : वे प्लेटफॉर्म जहाँ गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) झरवा गैर लाभकारी सामाजिक उद्यमों के लिए निवेशकों के माध्यम से धन एकत्र किया जाता है।

भारत में विनियम - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI)
↳ 2019-20 के बजट में घोषित।

आवश्यकता

- ① सामाजिक क्षेत्र में सरकार के साथ निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देना।
- ② सामाजिक उद्यमों में व्याप्त धन की कमी दूर करने हेतु।
- ③ निवेशकों को अपने धन का सामाजिक कल्याण में खर्च करने के विकल्प का सृजन
- ④ भारत में सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल आदि) में निवेश को बढ़ावा देने हेतु
- ⑤ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों और

संबंध निम्न दिशा निर्देशों (भाग-IV, UPSPs) को पूर्ति हेतु।

प्रभाव

- ① कोविड - 19 महामारी के पश्चात् सरकार पर खर्च का दबाव बढ़ा है ऐसे में निजी पूँजी जुटने से सरकार अन्य अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में निवेश कर सकेगी।
- ② निवेशकों में और लाभकारी संगठनों में विश्वास पैदा होगा → इन पर विनियमन होगा।
- ③ संगठनों पर प्रदर्शन में सुधार करने का दबाव होगा क्योंकि निवेशक इसके बाद निवेश की भाजा को बढ़ाएंगे।
- ④ भारत में सांस्कृतिक मूल्य जैसे - दान, जकात आदि के कारण के कारण भी इन्हे प्रोत्साहन मिलेगा।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज हमने पूर्व भी छाजील, यू.के., कनाडा आदि में सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। भारत में 20 लाख से भी अधिक सामाजिक उद्यम हैं जिसके वृद्धि तथा कार्यक्षेत्र को देखते हुए हमें मानकों का निर्माण कर सोशल स्टॉक एक्सचेंज जैसे निवेश के विकल्पों का निर्माण करना चाहिए।

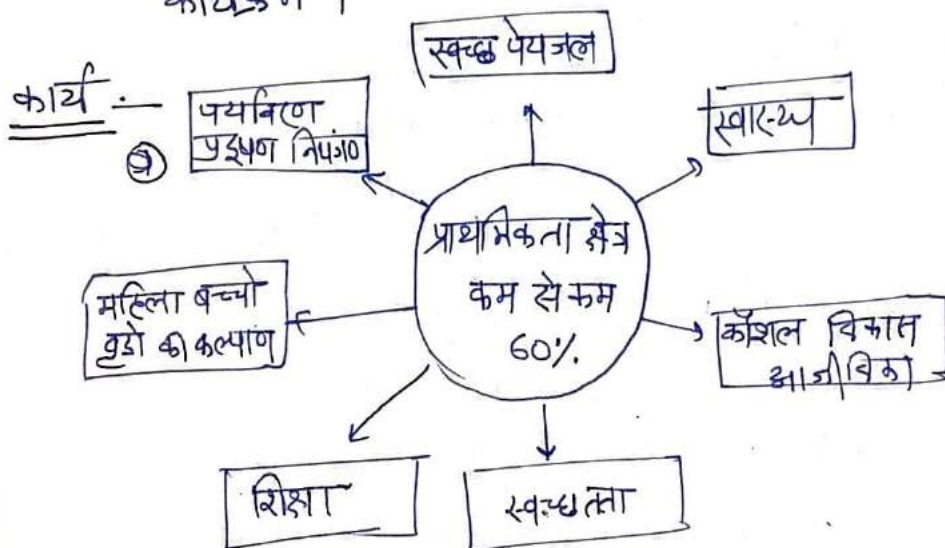
9. Broadly explain the composition and functions of the District Mineral Foundation (DMF). Also, discuss the issues in the effective utilisation of DMF funds. (150 words) 10

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की संरचना और कार्यों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। साथ ही, DMF निधियों के प्रभावी उपयोग के समक्ष मुद्दों पर भी चर्चा कीजिए।

खान और खनिज विकास अधिनियम, 2015 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक खनन कार्य वाले जिले में जैव लाभकारी संगठन के तौर पर जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी।

फंड → खनन कंपनियों द्वारा रॉयल्टी के 10-30% राशि के रूप में। (नॉन लेसेबल)

योजना - प्रधानमंत्री खनिज/खनन क्षेत्र कल्याण कार्यक्रम।



योजना निर्माण

डीएमएफ ट्रस्ट ग्राम सभाओं → अन्तिम कार्य
द्वारा योजना → द्वारा सुझाव → योजना
निर्माण
↓
राशि आवंटन

- मुद्दे**
- ① फण्ड का उपयोग सामान्य कार्यों के लिए होना, जबकि यह प्रभावित समुदाय के लिए है
 - ② प्रशासन, योजना और निवेश में गंभीर गड़बड़ियों का होना।
 - ③ दायित्व क्षेत्रों में अधिक खर्च जबकि इसकी सीमा 40% ही निर्धारित की हुई है
 - ④ जनभागीदारी का कमी तथा योजना का प्रसार अल्प होना।
 - ⑤ ग्राम सभा की भागीदारी बढ़ाने हेतु राज्यो द्वारा प्रयास न करना (सिवाय दक्षिणगोवा के)
 - ⑥ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने में चूक।

इस हेतु उल्लेख डीएमएफ की एक वेबसाइट होनी चाहिए जिस पर उल्लेख माह डाल जाये हो तथा वित्तीय औचित्यता के सिद्धान्त की अनुपालना हो। आदिवासी क्षेत्रों के रहवासियों के हितों और सामाजिक कल्याण को केन्द्रित योजना अनुच्छेद-46 की भावनाओं के अनुरूप भी है।

10. Illiteracy and poverty are hindrances in the formation of healthy public opinion on public policies. Discuss with suitable examples. (150 words) 10
निरक्षरता और निर्धनता सार्वजनिक नीतियों के संबंध में स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधक हैं।
उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए।

सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनसहभागिता होने से न केवल बेहतर नीति निर्माण होता है उसे लागू करने का भी दबाव प्रशासन पर बनता है।

परन्तु निरक्षरता (भारत में — 1%) तथा निर्धनता (तेंदुलकर कमिटी के अनुसार — 1%) ने नीति निर्माण की दिशा और दशा में परिवर्तन दिया है।

निरक्षरता से नीति निर्माण व जनमत निर्माण में बाधा।

- ① जनता में जागरूकता का अभाव → परिणाम बही
 - ② तथ्यात्मक रूप से व स्थानीय स्तरों के अनुरूप नीति निर्माण का न होना।
 - ③ शिकायत तंत्र का प्रयोग न कर पाने से अप्रचार तथा अकार्यक्षमता।
 - ④ नीति के डिपान्वयन पर नकारात्मक प्रभाव तथा लाभार्थी पूर्ण लाभार्थी न होना।
- उदा० - राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति → स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव → नीति निर्माण में भागीदारी कम → स्वास्थ्य अवसरों की कमी → कोविड-19 में बुरा असर

निर्धनता के कारण नीति निर्माण व जनमत निर्माण पर दुष्प्रभाव

- ① सही विषयो के बजाय पॉपुलर तरीके चुनना।
- ② नीति निर्माण में अव्यवस्था
- ③ व्यापक तौर पर अपमान के बजाय वोट बैंक आधारित नीति निर्माण
- ④ क्षमता निर्माण पर आधारित करने के बजाय तत्कालिक सहायता पर बल
- ⑤ आम बल की उत्पादकता में गिरावट → अन्य क्षेत्रों में भी नकारात्मक प्रभाव

उदाहरण:- निर्धनता ↑ → रोजगार ↑ → उत्पादकता ↑
पेंशन/सहायता ↑ → राजकोष
उदा. - बेरोजगार भरा ↑
भरा

अतः नीति निर्माण में निम्न विकल्पों पर ध्यान रखा जाना चाहिए -

- ① अविलम्ब में विक्रीप भाट न बने
- ② क्षमता निर्माण करे ताकि गरीबी मुक्त कर सके
- ③ गरीबी हमी ^{सामाजिक} नीतियों का मूल है जिससे निरक्षार तथा कुपोषण जैसे उल्लेख होते हैं उन्हें हमल नश करे।

अतः ऐसी योजनाएँ जैसे - पीएम स्किन

इंडिया, शिक्षा नीति - 2020 में क्षमता निर्माण पर बल आदि को बढ़ावा देना चाहिए।

11. A critical appraisal of the outcomes of the 74th Constitutional Amendment Act underlines the need for second-generation reforms to strengthen decentralisation of urban local governance in India. Discuss. (250 words) 15
- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भारत में शहरी स्थानीय शासन के विकेंद्रीकरण को मजबूत करने हेतु दूसरी-पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। चर्चा कीजिए।

74 वें संविधान संशोधन, 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग-9A (अनुच्छेद 243पी - 243 डी) तथा अनुसूची-12 को जोड़कर शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्व-शासन लागू किया गया।

शहरी स्थानीय स्वशासन के सकारात्मक परिणाम

- ① आम जन की सहभागिता में वृद्धि।
- ② नियमित चुनावों से राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि।
- ③ सहयोग, जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास
- ④ आरक्षण का प्रावधान → समावेशी प्रतिनिधित्व
- ⑤ राज्य क्ति आयोग → विनियम अधिकारों तथा हस्तांतरण में वृद्धि।
- ⑥ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीति निर्माण

नकारात्मक परिणाम

- ① व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार → मणिशंकर अय्यर समिति द्वारा इसे भ्रष्टाचार का विदेन्ट्रीकरण कहा।
- ② विनीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं।
↳ अभी भी राज्यों के अनुदान पर निर्भर
- ③ वित्तीय स्रोतों का आवंटन नहीं।
↳ कर लगाने वाली शक्ति का हस्तांतरण न होना
अथवा चुनावी लाभ हेतु कण्टेपग न करना।
- ④ कार्मिकों का अभाव → कर्मचारियों की कमी
↓
- ⑤ प्रतिनिधियों को उचित प्रशिक्षण नहीं होना।
↳ प्रशिक्षण की जानकारी का अभाव
↳ अधिकारियों की मनमर्जी का बढ़ना
- ⑥ शहरी निकायों को ~~सबसे~~ बाह्यी अनुसूची के अनुरूप कार्यों का हस्तांतरण न होना
- ⑦ राजनीतिक हस्तक्षेप का होना।
- ⑧ अन्य निकायों की स्थापना से इनके कार्यों को कम महत्व — शहरी विकास प्राधिकरण
— बिजल - पानी प्राधिकरण,
— ~~अन्य~~ स्मार्ट सिटी कंपनी

दूसरी पीढ़ी के सुधार व उनकी आवश्यकता

- ① राजनैतिक हस्तक्षेप में कमी लाना तथा निकायों की स्वायत्तता को बढ़ाना।
- ② प्रातिनिधिकों व कामियों के परीक्षण के तंत्र को विकसित कर उन्हें विरवस्तरीय परीक्षण देना।
- ③ विरवस्तरीय शहरी निकायों से जोड़ना।
लवारायसी - कपोले आदि।
- ④ योजनानिर्माण में भागीदारी तथा विशेषसेवाएँ उपलब्ध कराना।
- ⑤ विनीय स्रोतों को विकसित करना तथा अवाकदेही और ई-गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार पर नकल करना।

शहरी निकायों की विरवस्तार पर तुलना करने पर बात काफी इत नजर आता है जबकि 30 प्रतिशत आबादी और 65 फीसदी जीडीपी का हिस्सा यही है। स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, स्वयं सहायता शहर निर्माण जैसी योजनाओं में स्थानीय निकायों की भागीदारी ले ही ~~करने के~~ सतत विकास लक्ष्य सज्वा - 11 सतत शहर और समुदाय को प्राप्त किया जा सकता है।

12. Asymmetry is an important characteristic of federalism in India, which has helped in the accommodation of diverse demands inherent in our democracy. Discuss. (250 words) 15

असममिति भारत में संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसने हमारे लोकतंत्र में निहित विविध मांगों के समायोजन में सहायता प्रदान की है। चर्चा कीजिए।

भारत में असममिति संघवाद संघ का गठन करने वाली इकाइयों के बीच राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय व्यवस्थाओं में असमान शक्ति वितरण पर आधारित संघवाद।

① 5वीं अनुसूची — अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान
↳ 10 राज्यों के कुछ क्षेत्र

② 6वीं अनुसूची — अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में
↳ स्वयं शासन जिला परिषद का गठन
↳ असम — 3 ; काबी ऐबलोंग, कुरी कछार, बौडोलेण्ड
↳ मिजोरम — 3 ; चक्मा, लाई, मारा
↳ त्रिपुरा — 1 ; त्रिपुरा पहाड़ी
↳ मेघालय — 3 ; गारो, खासी, जयंतियाँ

③ विशेष राज्य का दर्जा — केन्द्र द्वारा केन्द्रीय योजनाओं में
↳ सामान्य — 60:40 केन्द्र राज्य में अधिक हिस्सेदारी
↳ विशेष — 90:10

④ अनुच्छेद — 371 — के तहत राज्यों में विशेष प्रावधान
अव० — 371 — महाराष्ट्र — गुजरात हेतु
अन० A = नागालैण्ड का त्वेनसांग जिला

⑤ राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व

⑥ वित्त आयोग 51 अनु०-275 के अनुसार विशेष अनुदान की व्यवस्था

- ⑦ धार्मिक, सामाजिक - सांस्कृतिक, भूस्वामित्व, प्रयागत कानूनों की संरक्षण। -
- ⑧ केन्द्रशांति प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी तथा दिल्ली में अंतर लोकतंत्र में विविध मांगों के समायोजन में सहायक
- ① सामाजिक न्याय - अलग-अलग वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधान
- ② विविधता में एकता को बढ़ावा - कमजोर समूह की रक्षा कर विविधता का सम्मान
- ③ अधिकारों का संरक्षण - मौलिक अधिकार अनु० - 29, 30, 25 आदि का रक्षण
- ④ कट्टरता को कम करने में - जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत में आतंरिक विरोधी गतिविधियों को रोकने में।
- ⑤ जनसहभागिता बढ़ाकर लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

हालांकि इस असमानिती संघर्ष ने कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं जिनमें

- ① राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व का धोरे (ज्यो दार विरोध)।

- ② विशेष दर्जे की मांग का ^{सबसे} राज्यों द्वारा भी-
मांग रूला। उदा० - राजस्थान, महाराष्ट्र
- ③ पूर्वोक्त में विभिन्न आदिवासी समूहों में
प्रथाओं में ही विरोधाभास होना ही हिंसा होगा।
- ④ समूह विशेष को विशेष स्थितियाँ देने पर
अन्य समूहों द्वारा विरोध; जिससे अलगाववाद
की श्रृंखला का बनना

अतः राज्यों के बीच असमान
स्थिति असममिति संबंधों को जन्म देती है तथा
असमानता के कारण उत्पन्न असंतोष को
समाप्त करती हैं। ~~सबसे~~ ~~प्रधान~~ एक
~~विषय~~ और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विश्वास
बढ़ाती हैं।

13. It is argued that unchecked and rampant exercise of the power to insert laws in the Ninth Schedule results in undermining of Constitutional supremacy and creation of Parliamentary hegemony. Do you agree? Justify your stand with logical arguments. (250 words) 15

यह तर्क दिया जाता है कि नौवीं अनुसूची में विधियों को सम्मिलित करने की शक्ति के अनियंत्रित और व्यापक स्तर पर प्रयोग से संवैधानिक सर्वोच्चता में कमी और संसदीय आधिपत्य का मृजन होता है। क्या आप सहमत हैं? उचित तर्कों के साथ अपने मत की पुष्टि कीजिए।

प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इसमें भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु राज्यों के व केन्द्र के कानूनों को रखा गया।

~~केन्द्र के कानूनों को~~ भारतीय संविधान, 1973 में संसदीय आधिपत्य का सृजन करता है, क्योंकि -

1. मौलिक अधिकारों को हनन किया जा सकता है।
2. अनुच्छेद-13 में वर्णित विधि की सीमाओं से बाहर होना।
3. अनु-32 तथा अनुच्छेद-226 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को प्राप्त हितों का प्रयोग नहीं हो सकता।
4. संविधान के मौलिक आदर्शों और अधिकारों का उल्लंघन।
5. सरकार/संसद में एकाधिकार की भावना बढ़ती है।

6. संविधानवाद को कमजोर करती है,
7. लोकतंत्र के मुख्य मूल्य - संतुलन को असंतुलित करती है (चेम्स एंड कंपनी)

हालांकि वामन राव वाद, 1981

तथा आई.आर. कोएल्हो वाद, 2007 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल, 1973 के पश्चात शामिल सभी 9वीं अनुसूची के कानूनों का न्यायिक परीक्षण हो सकता है यदि वे अनुच्छेद -14, 19 और 21 के साथ मूलभूत विशेषताओं का उल्लंघन कर रहे हैं।

इसके कई प्रभाव पैदा हुए हैं जैसे -

1. न्यायिक समीक्षा के क्षेत्राधिकार में वृद्धि
2. सत्सदीप सर्वोच्चता के अनाय संवैधानिक सर्वोच्चता
3. सरकार की मनमर्जी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही
4. संविधानिक की मूलभूत विशेषताओं की रक्षा
5. मौलिक अधिकारों का रक्षण ।

हालांकि कई समीक्षकों ने इस पर सिंता भी
जताई थी कि -

1. 9वीं अनुसूची के कानून भाग-IV दिशानिर्देशों
तत्वों को प्रभावी बनाते हैं -

- जैसे अनु-39(b) (असाधनों का सम वितरण
2. सामाजिक न्याय को स्थापित करते हैं)
3. सुभेद्य वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं
4. सरकारों के चुनावों में दिए वादों की पूर्ति सुनिश्चित
करते हैं

श्रीगोंगे की राह

1. मिनर्वी मिल्ल काद में उच्चतम न्यायालय ने
दिशानिर्देशों तत्वों व मौलिक अधिकारों के
संतुलन को संविधान की माध्यात्म विशेषता
स्वीकारा है।

अतः संसदीय अधिपत्य अथवा
न्यायिक अधिपत्य के बजाय संवैधानिक
अधिपत्य को स्वीकार किया जाना चाहिए।

14. Though the antecedents of the Indian Constitution can be traced to a series of British colonial legislations and other Constitutions of the world, in spirit and practice it has been completely Indian. Discuss. (250 words) 15

यद्यपि भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनों की शृंखलाओं और विश्व के अन्य संविधानों में देखी जा सकती है, तथापि सिद्धांत और व्यवहार में यह पूर्णतः भारतीय है। चर्चा कीजिए।

26 नवम्बर 1949 को पारित भारतीय संविधान को कई आलोचकों ने उधार का संविधान बताया है। क्योंकि भारतीय संविधान में कई ऐसे तत्व हैं जो विदेशी संविधानों से लिए हैं। जैसे -

स्रोत	विषय
भारत शासन अधिनियम 1935	संघीय शासन, न्यायपालिका प्रशासन, सीएजी, लोक सेवा आयोग
ग्रेट ब्रिटेन	संसदीय शासन, विशेषाधिकार विधि का शासन, एकल नागरिकता
संयुक्त राज्य अमेरिका	मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग
कनाडा	संघात्मक शासन, अवशिष्ट शक्तियाँ - केंद्र
हायरलैंड्स	नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनीति
दक्षिण अफ्रीका	संविधान में संशोधन राज्यसभा का नियोजन
फ्रांस	समता, स्वतंत्रता, बहुता तथा गणतंत्र
रूस	मौलिक कर्तव्य, सामाजिक न्याय
जर्मनी	आपातकाल में मूल अधिकारों का निषेध
जापान	विधि द्वारा स्थापित उद्दिष्ट
ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची, संयुक्त अधिकार

उपरोक्त भाषारो पर संविधान सभा के सदस्य के. एनमधैया ने कहा — हम भारतीय बीणा का स्वर सुनना चाहते थे, लेकिन यह इंग्लिश वॉल का संगीत सुना रहा है। साथ ही उन्होंने इसे गांधीवादी सिद्धान्तों का विरोधी संविधान भी बताया।

इस आलोचनाओं का जवाब डॉ॰ अम्बेडकर ने दिए —

① संविधान निर्माण एक शाश्वत परंपरा है जो अलग-अलग समय पर देश बनाते हैं। नवीनतम संविधान निर्माता राष्ट्र यह सुनिश्चित करते हैं कि पुराने संविधान की गलतियाँ न हो तथा अच्छी बातें समाहित हो।

② संविधान के मौलिक विचार (मूल अधिकार, कर्तव्य, न्याय, समानता, लोकतंत्र) भाँट पर किसी का अधिकार नहीं है।

③ सभी प्रावधानों का भारतीय संस्कृति के अनुरूप संविधान बन गया है जैसे —

अनुच्छेद-6 विशेष अनुसूचित जनजातियों हेतु

④ सभी धर्मों को सम्मान देने की परंपरा तथा
मम नार्यस्तु पूज्यन्ते तस्मै देवता की

- आवनानुरूप महिला - बच्चों हेतु विशेष प्रावधान
- ⑤ शिक्षा हेतु स्थानीय भाषा का प्रावधान
व भाषा संरक्षण — अनुच्छेद 350 A तथा B
 - ⑥ भौगोलिक अलगावों को सम्मान कहे हुए
विशेष राज्यों का प्रावधान तथा ~~अलग~~ राज्य व
संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन
 - ⑦ पर्यटक मताधिकार तथा सुमेध कर्गों हेतु विशेष
प्रावधान ।
 - ⑧ धर्मनिरपेक्षता का भारतीय स्वरूप — सभी धर्मों को समान
(सर्वधर्म समभाव)

उपरोक्त आधारों से स्वीकारा जा सकता है
भारतीय संविधान में विदेशी तत्व का भारतीयकरण
करके ही उन्हें शामिल किया है । भारतीय
संविधान एक गतिशील जीवंत दस्तावेज है जिसे
लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए
डिजाइन किया है और यह तीसरी दुनिया
के उभरते लोकतांत्रों के लिए भी प्रेरणादायी है ।

15. In India, the Finance Commissions are established pursuant to the constitutional mandate. In this context, do you think the State Finance Commissions have been effective in promoting fiscal federalism? Substantiate with arguments. (250 words) 15

भारत में वित्त आयोगों की स्थापना संवैधानिक अधिदेश के अनुसार की जाती है। इस संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि राज्य वित्त आयोग राजकोपीय संघवाद को बढ़ावा देने में प्रभावी रहे हैं? तर्कों के साथ पुष्टि कीजिए।

— राष्ट्रपति द्वारा, प्रत्येक 5 वर्ष में
संघीय वित्त आयोग → अनुच्छेद - 280

- ① संघ राज्यों में करो का वितरण
- ② राज्यों-राज्यों में धन वितरण
- ③ पंचायती राज सत्यामों को अनुदान
- ④

राज्य वित्त आयोग (राज्यपाल द्वारा) प्रत्येक 5 वर्ष में
— अनुच्छेद - 243 (I) तथा -

- अनुच्छेद - 243 (Y) के द्वारा एक ही।
- ① राजपसकाल व पंचायतो में करो का बंटवारा
 - ② पंचायतों के करो, शुल्को का निर्धारण
 - ③ अनुदान
 - ④ विनीप सुधार हेतु आवश्यक कदमों की अनुशंसा

राज्य वित्त आयोग ने राजकोपीय संघवाद बढ़ाया है

- ① तृणमूल स्तर तक विनीप आवंटन
 - ② राज्य से स्थानीय निकायों को धन का हस्तांतरण
 - ③ 11वीं तथा 12वीं अनुसूची के कार्यों का आवंटन
- तथा उन्हें कलै हेतु शुल्क व करो का कार्यभार सौंपना। उदा० - नगरीय विकास का (UDTx)

- ④ केन्द्रीय वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग के अनुदान प्राप्त होंगे
- ⑤ राज्य की नीतियों की सफलता स्थानीय निकायों पर निर्भर होगा। उदा. - स्मार्ट सिटी, अमृत सिरी - आदर्श ग्राम योजना

⑥ राजकोषीय संघराढ़ कमजोर हुआ है

- ① संविधान की मूल भावना के अनुरूप पंचायतें आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हुई हैं।
- ② राज्य वित्त आयोग को गठन या तो समय पर नहीं होता है अथवा उनकी अनुशंसकों को अस्वीकार कर दिया जाता है।
- ③ अनुदान पर अधिक निर्भर
- ④ मध्यवर्ती तथा जिला पंचायत आर्थिक रूप से अयोग्य।
- ⑤ श्रमधारा की बढ़ती मांग
- ⑥ प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक।

आगे की राह

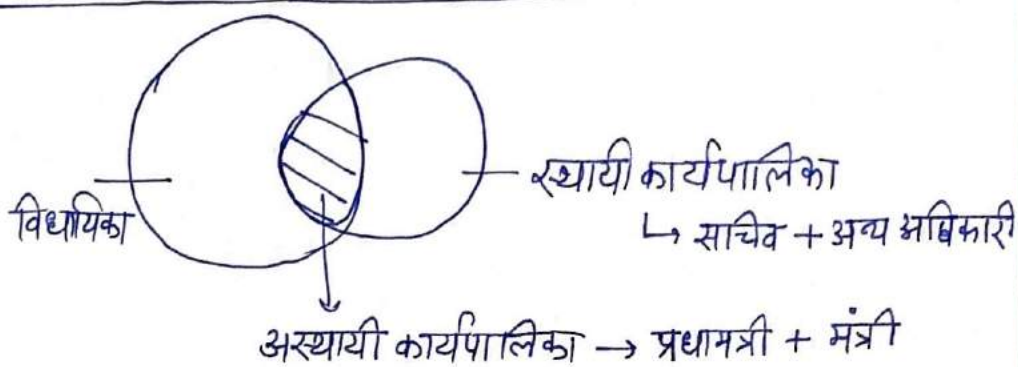
- ↳ ① नियमित रूप से विनीय आवंटन
- ↳ ② पारदर्शिता हेतु सामाजिक ऑडिट तथा ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना।

- ③ जिम्मेदारियों के साथ संसाधनों
का विकेंद्रीकरण तथा उचित स्तर
पर जवाबदेही तंत्र का विकास
- ④ करो की बाध्यता विकसित करना
ताकि अनुरानों पर निर्भरता कम हो।
- ⑤ प्रदर्शन आधारित आवेदन को बढ़ावा।
- ⑥ अनुराणों बाध्यकारी हो भयवा पालन न करने
के कारण सावर्गनिक हो।
अतः अनुच्छेद - 40 (क) मावना
व गाँधीजी के दर्शन को प्रतिबिम्बित
प्रायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण
आर्थिक सशक्तिकरण पर निर्भर है। इस हेतु
राज्य वित्त आयोग में सुधार (क) नितांत
आवश्यकता है।

16. In India's political system, the Executive and Legislature are not strictly separated; instead, their relationship is intimate and non-dichotomous.
(250 words) 15
Comment.

भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, कार्यपालिका और विधायिका पूर्णतः पृथक नहीं हैं, अपितु इनके मध्य अभिन्न एवं अविच्छेद संबंध हैं। टिप्पणी कीजिए।

भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है ; जिसमें कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है।



चित्र : भारतीय विधायिका और कार्यपालिका में सम्बन्ध

कार्यपालिका और विधायिका में संबंध

- ① कार्यपालिका (अस्थायी), निम्न सदन के प्रति जवाबदेह होती है। (अनुच्छेद - 75) [सामूहिक उत्तरदायित्व]
- ② प्रश्नकाल, चर्चा आदि के माध्यम से

कार्यपालिका के व्यवहार को नियंत्रित करती है।

③ संसदीय समितियों के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों, वित्तीय सूचनाओं, योजनाओं आदि पर दिशा निर्देश जारी करती है।

④ निदा प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकारी योजनाओं या मंत्रियों के प्रति भविष्यवाणी प्रकट करती है।

⑤ कार्यपालिका के कार्यों के लिए अधिनियमों का निर्माण करना। ⑥ अध्यादेश द्वारा विधिनियम

⑥ कार्यपालिका विधायिका में प्रथमकरण ^{L भू-123}

⑦ इंदिरा गांधी वनाम राजनारायण वाद, में उच्चतम न्यायालय में शक्ति प्रथमकरण को व्यापक हदों में देखा।

① संसद की सम्प्रभुता, जब तक कि वह संविधान का उल्लंघन न करे।

② कार्यपालिका को नीति निर्माण के लागू करने में स्वतंत्रता।

③ अधिकारियों के वेतन - भत्ते, स्थानान्तरण आदि का अधिकार।

- ④ कार्यकारी आदेशों तथा - कैबिनेट कमिटी की निर्माण क्षति में विधायिका की सीमित होगा।
- ⑤ विधायिका के भीतरी कार्यों में कार्यपालिका की सहस्त्रक्षेप ।

भाग 3 राह

- ① एक लोकतांत्रिक सरकार और भारत में विविधताओं से भरे देश में शक्ति की पूर्ण विभाजन ~~का~~ अवांछनीय और अव्यवहारिक है।
- ② आपसी सहयोग सरकार की कार्यपालिका और विधायी शाखा के बीच दूरियाँ कम करने के साथ ही चेम्स एन्ड वेल्लेन्स (संतुलन - प्रतिस्पर्धा) बनाए रखने में भी मदद करता है।

17. Reduction in the overall size of the bureaucracy has been seen as the underlying idea behind civil services reforms. Is it a good idea to reduce the size of the Indian bureaucracy? Examine in light of the experience of India.

(250 words) 15

नौकरशाही के समग्र आकार में कमी को सिविल सेवाओं में सुधार के पीछे अंतर्निहित विचार के रूप में देखा गया है। क्या भारतीय नौकरशाही के आकार को कम करना एक उपयुक्त विचार है? भारत के अनुभव के आलोक में परीक्षण कीजिए।

लोकसभा में दिए प्रश्न के जवाब में बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में 22% पद रिक्त हैं।

हालांकि कई बार नौकरशाही के आकार में कमी को सिविल सुधारों से जोड़ा जाता है क्योंकि —

- ① रिक्त पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती कहे विशेषज्ञों को भर्ती किया जा सकेगा।
- ② परंपरागत नीति निर्माण से मुक्ति मिलेगी।
- ③ अधिकृत नौकरशाह प्रशासनिक जटिलताओं में छूट करते हैं।
- ④ बेहतर गवर्नेंस हेतु ई-मॉडल्स अपनाना
- ⑤ आउटसोर्सिंग आदि आवश्यकतानुसार कार्रवाइ की जाएगी।

हालांकि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने बताया कि इनके आकार में कमी के बजाय अन्य सुधारों को लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि इनकी कमी करने का विकल्प नहीं है —

~~कुछ~~

- ① विशाल आकार और विविधता युक्त देश
- ② अभी सरकार प्रस्तुत सेवाएँ न तो ऑनलाइन हुई हैं और न ही सभी उसे प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं
- ③ अस्थायी कार्यपालिका और विधायिका को उचित मार्गदर्शन देने हेतु।
- ④ राजनीतिक तरस्थता को बनाए रखने हेतु।

भारतीय नागरशाही में कई सुधार अपेक्षित हैं — जैसे —

- ① औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त और निष्पक्ष, पारदर्शी तथा समतामूलक प्रशासन देना।
- ② वर्तमान युग की अपेक्षाओं पर आधारित नागरिक केन्द्रित शासन, ई-शासन, आधारित शासन प्रदान करना।

- ④ रिफॉर्म से ट्रान्सफॉर्म की ओर जानो
- ⑤ नवकारी तथा एजेंट फॉर चेंज की भूमिका अपनाना।
- ⑥ रेगुलेटर से फैसिलिटेटर की भूमिका में आना।

इसी को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएँ तथा तंत्र विकसित किए हैं जैसे -

① मिशन कर्मयोगी -

- ② विशेषज्ञीकरण को बढ़ावा हेतु क्रि बैटल एण्ट्री
- ③ भर्ती प्रक्रिया में सुधार हेतु वासवन्ना तथा होता समिति की सिफारिशों लागू करना।
- ④ गुड गवर्नेंस पर नागपुर घोषणा का तथा ई गवर्नेंस पर हैदराबाद और शिवांग घोषणा का
- ⑤ 360° अप्पेनल व्यवस्था
- ⑥ सीपीजीआरएमएस के माध्यम से वेन्यूहट शिकाया प्रणाली।

लोकसेवकों अथवा नॉकरशाही की संख्या की कमी को देखते हुए और कमी कला जायज नहीं है; इसके बजाय इसी व्यवस्था में सुधार कला चाहिए मसलन 2010 में प्रस्तावित मिबिल सर्विस स्टैंडर्ड्स परफॉमेंस एंड एकाउंटिबिलिटी बिल को लागू करना आदि। तारी 21वीं सरी 2 अनुसूप नॉकरशाही में बनाया जा सके।

18. There is a need to ensure better ethical standards, accountability and management of temples in India. Discuss in the context of issues associated with state intervention in management of temples. (250 words) 15

भारत में मंदिरों के बेहतर नैतिक मानकों, जवाबदेही और प्रबंधन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मंदिरों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

हाल ही में कई वर्गों ने मंदिरों में
(संगाना)
सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध मांग उठाई है तथा
अनुच्छेद-26 के समान ही हिन्दू मंदिरों का संचालन
हिन्दू संस्थाओं की मांग की है।

मंदिर प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता।

- ① संवैधानिक आधार - अनु-25(6) अनुदेशित करता है कि राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार हेतु हिन्दू संस्थाओं को संचालित कर सकता है।
- ② बहुसंख्यक समुदाय के हितों को रक्षा हेतु
- ③ मंदिर प्रशासन में व्याप्त धन संग्रहण को रोककर जनहित में खर्च करने हेतु।
- ④ दानदाताओं के हितों और भक्तों के हितों के संरक्षण हेतु।
- ⑤ असामाजिक प्रथाओं जैसे - दूआछूत, देवादासी आदि को रोकने हेतु।
- ⑥ नैतिक मानक जैसे - जवाबदेही, पारदर्शिता सुव्यवस्थित प्रबंधन, भक्तों के आगमन में

सुविधा, ठहरने-पेयजल - स्वस्थता की सुविधा, आवागमन के साधनों का विकास, चिकित्सा की व्यवस्था का प्रबंधन आदि।

(7) श्रष्टा व्यवस्था को रोकने और कर्मकाण्डी-प्रथाओं को रोककर धार्मिक अध्यात्मिक उन्नयन करना।

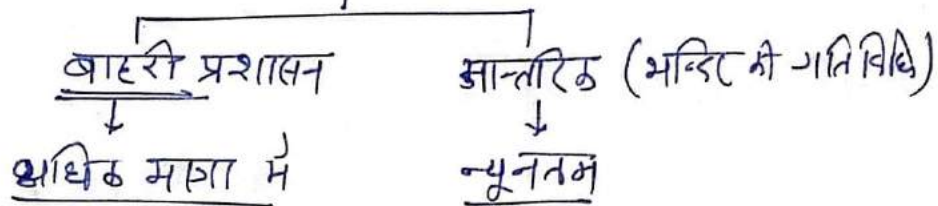
मुद्दे

- ① धर्मनिरपेक्षता से भटकाव → राज्य की धर्म में हस्तक्षेप
- ② अधिकारियों का मन्दिर बोर्डों पर कब्जा
उदा० - तिरुमाला बोर्ड
- ③ मन्दिर बोर्डों का राजनीतिकरण
उदा० - केदारनाथ देवस्थान बोर्ड विवाद
- ④ महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा
↳ सखरीमाला मन्दिर विवाद
- ⑤ मन्दिर व्यवस्थाओं का कुप्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन की अभाव - केरल में 2016 में पुन्निगल मन्दिर आग से 100 से अधिक की मौत
- ⑥ मन्दिर की आन्तरिक परम्पराओं में ~~वैक~~ अनुचित हस्तक्षेप। उदा० - जावहार मन्दिर विवाद

अतः राज्य को मन्दिर के प्रबंधन में एक संगठित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विभिन्न राज्यों द्वारा ही मन्दिर बोर्ड का गठन किया है, परन्तु केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

भागों की राह

① मन्दिर प्रबंधन में न्यूनतम हस्तक्षेप



② पारदर्शिता का बढ़ाना

③ गैर राजनीतिक लोगों तथा उन्नीस समुदाय के लोगों की भागीदार बनाया जाना चाहिए।

④ केन्द्रीय स्तर पर स्टैंडर्ड मानक विकसित होने चाहिए तथा बोर्ड को स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

अतः सामाजिक नैतिक मानकों

और प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए राज्य को मन्दिरों में हस्तक्षेप न केवल संवैधानिक तथा नैतिक रूप से भी उचित है वरन् वह उस मन्दिर की मूल परंपराओं को उल्लंघन न करे।

19. Over 15 years of the Right to Information Act have thrown up multiple experiences, some of which need to be built upon, while others necessitate steps to uphold the act in its letter and spirit. Explain with examples.

(250 words) 15

सूचना का अधिकार अधिनियम के 15 वर्षों ने अनेक अनुभव प्रदान किए हैं, जिनमें से कुछ के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है, जबकि अन्य अधिनियम को उसकी मूल भावना के अनुसार बनाए रखने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ाने वाले सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को संसद द्वारा पारित किया। ~~कहते हैं~~ सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी है; जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा हमदर्द उवाखाना वाद में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत माना है।

सूचना के अधिकार के सकारात्मक प्रावधान तथा उनके प्रभाव।

- ① अस्वाचार के मामलों को उजागर करने में
उदा. - कॉमनवेल्थ, कोल, एनआएनएम घोषणा
- ② शासन-भ्रष्टाचार गड़बड़ उजागर करने में
③ — याचना पूँजीवाद
- ③ सूचना के स्वच्छ प्रकटीकरण (section 4)
से स्वतः जवाबदेही का विकास
- ④ समयबद्ध तरीके से जानकारी देने से प्रशा-
सनिक विश्वास तथा कार्यक्षमता में वृद्धि

- ⑤ प्रशासनिक अपव्यय के मामले उजागर
उदा० - सरकारी बजट पर विदेश भ्रमण, पार्लिंग
- ⑥ सूचित समाज को जन्म दिया है। एक
अमिदुनि विमलित को है जो लोकसंग्रह के
मूल्यों को बचावा देती है।

- ⑦ गोपनीय सत्तुति से पारदर्शी संस्था
के रूप में।

हालांकि सूचना के अधिकार के तहत कुछ
प्रावधान ऐसे हैं जिन्होंने ~~नकारात्मक~~ हमारी
मूल भावना के विपरीत प्रभाव डाला है -

- ① Section-4 : स्वैच्छिक प्रकटीकरण का ~~कोई~~
अनिवार्य नहीं होना। सूचना आयोग के अनुसार
85 संसदों ने किसी प्रकार ही सूचना प्रकट नहीं की।
- ② Section-8 - का दुरुपयोग → देश की संप्रभुता
एकता-अखण्डता आदि आधारों की सीमा निर्धारित
न होने से अधिकारियों और इसका दुरुपयोग।
- ③ गोपनीयता अधिनियम की आड़ में सूचना पर
रोक
- ④ प्रशासनिक तंत्र को सुविमलित नहीं मिला।
- ⑤ आर्टीआई को बैलेंसमेल अथवा पॉपुलैरिटी के
लिए प्रयोग में लाना।
- ⑥ आर्टीआई द्वारा निजता में प्रवेश। (Section 4 की
भावना का उल्लंघन)

अतः आरटीआई अधिनियम से सुधारों की गति को तीव्र करना चाहिए जैसे —

- ① गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों को कम कर जवाबदेही आधारित आरटीआई को मजबूत बनाना
- ② Section-4 को अनिवार्य लागू करना
- ③ Section-8 के आधार को सीमित व परिभाषित करना
- ④ Section-11 के आधार पर निरन्तरता की रक्षा करना
- ⑤ हालिया संशोधन, 2019 में परिवर्तन कर सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता को बढ़ाना।

एक पारदर्शी, निष्पक्ष, तटस्थ, जवाबदेह प्रशासन ही ईमानदार और सत्यनिष्ठ शासन हो सकता है। आरटीआई ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे साबित तो किया है परन्तु इसका विस्तार और स्वायत्तता को अभी विकसित करने की और अधिक जरूरत है।

20. The issuance of Citizens' Charters alone cannot change the mindset of staff and clients overnight; rather, regular, untiring and persistent efforts are required to bring about attitudinal changes. Discuss. (250 words) 15

केवल सिटीजन चार्टर जारी करने से कर्मचारियों और ग्राहकों की मानसिकता में ऐकांगक परिवर्तित नहीं किया जा सकता; बल्कि व्यवहार में बदलाव लाने के लिए नियमित, अथक और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

सिटीजन चार्टर : सरकार के मंत्रालय या संगठन द्वारा जनता को प्रदत्त लोकसेवाओं की सूची जो समयबद्ध व गुणवत्तात्मक रूप से निःशुल्क/सशुल्क हो, तथा नही प्रदान करने पर शिकायत तन्त्र की स्थापना सिटीजन चार्टर कहलाता है।

प्रभाव

- ↳ प्रशासनिक जवाबदेही को विकसित होती है
- ↳ ग्राहकों को उचित मूल्य और गुणवत्ता की सेवा प्राप्त होती है
- ↳ विश्वसनीयता और आत्मनिष्ठता का विकास होता है
- ↳ लोकतांत्रिक मूल्यों में बृद्धि होती है

हालांकि केन्द्रीय स्तर पर सिटीजन चार्टर विकसित नहीं हुआ है, ~~अब~~ आपित कई राज्यों ने इसे अपने-अपने स्तर पर बनाया है। 2nd ARC के रिपोर्ट ने इसे अधूरे मन से लिए प्रयास बताया है।

कारण

- ↳ प्रशासनिक मनोवृत्ति का अभाव
- ↳ राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव

- ④ सांस्कृतिक विरोधाभास
- ⑤ तकनीक तथा संरचनात्मक विकास का अभाव
- ⑥ विधिक तार्किकता का अभाव
- ⑦ नागरिकों की जागरूकता, क्षमता, इच्छाशक्ति और अवसर का अभाव

अतः केवल लिबिजन-पार्टी
जारी करते ले कर्मचारियों और ग्राहकों की
मानसिकता परिवर्तित नहीं हो सकती है क्योंकि -

- ① पूर्णतः पालन नहीं हो पाता तथा प्रकाशन गलत
- ② भाषायी समस्या
- ③ मानकीकृत न होना
- ④ शिकायत तंत्र संक्षिप्त न होना आदि।

इसके लिए व्यवहार में बदलाव
लाना आवश्यक है जैसे -

- ① कार्य प्रेरण करना
 - धनात्मक - धन प्रदान करना, पुरस्कार देना
 - ऋणात्मक - दण्ड देना, डांटना
 - अमौलिक - प्रशंसा करना, उदार अवकाश नीति
- ② ~~कार्य~~ कार्यों से उत्पन्न प्रभावों से अवगत कराकर सम्प्रेषी (करुणा) उत्पन्न करना
- ③ उन्हें एक सकारात्मक कार्य संस्कृति से परिचित करवाना।

- ③ विधिक जवाबदेही के साथ-साथ आंतरिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना।
- ④ टीम वर्क, रचनात्मकता, ई गवर्नेंस जैसे उपकरणों का प्रवेश
- ⑤ निरंतर प्रशिक्षण तथा पर्यवेक्षण करना।
- ⑥ व्यक्तिगत अंतर की पहचान करना
- ⑦ रोल मॉडल विकसित करना।
- ⑧ थ्रोटको में सिखण की परंपरा विकसित करना
- ⑨ चार्टर आदि को बहुभाषी तथा सरल शब्दों में लिखना
- ⑩ लचीला तथा समानुभूति प्रशासन उपलब्ध करना
- ⑪ जागरूकता का प्रसार कर अवसर उपलब्ध करना।

बाह्य दबाव से उत्पन्न परिवर्तन स्थायी होते हैं यदि यह आंतरिक रूप से उत्पन्न होता न केवल स्थायी बल्कि क्रांतिकारी परिवर्तन भी स्थापित करते हैं, जिनकी भारतीय शासन प्रणाली में उचित मूल्यों के रूप में आवश्यकता भी है।